



*Mahendra's*



**UP POLICE कांस्टेबल / UP लेखपाल 2021**



**GK/GS**

**CHRISTMAS SPECIAL  
CLASS**



**LIVE**

**02:00 PM**



- Q1. WHO AMONGST THE FOLLOWING IS CONSIDERED TO BE THE FIRST LAW OFFICER OF THE GOVERNMENT OF INDIA ?
- Q1. निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है?
  - A. CHIEF JUSTICE OF INDIA भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - B. SOLICITOR GENERAL OF INDIA सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया
  - C. ATTORNEY GENERAL महान्यायवादी
  - D. CAG



## ANSWER : C

- Article 76 of the Indian Constitution under its Part-V deals with the position of Attorney General of India.
- President of India appoints a person who is qualified for the post of [Supreme Court](#) Judge.
- There is no fixed term for the Attorney General of India
- He got the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of Parliament

1st Attorney  
General

M.C. Setalvad

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके भाग-V के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है।
- भारत के राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है।
- भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है
- उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार मिला



- Q2.THE TENURE OF CAG IS
- Q2.नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है

- 5YEARS
- 6YEARS
- NOT FIXED
- 4YEARS

## ANSWER : B 6 YEARS

- The Comptroller and Auditor – General of India is appointed by the President. He holds office until he attains the age of sixty-five years or at the expiry of the six-year term, whichever is earlier. He submits an audit report of the Union to the President who shall lay it before the Parliament and the audit reports of the States to the respective Governors who shall lay it before the respective State Legislatures.
- Article 148 of the Constitution of India establishes the authority of this office.

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या छह वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को संघ की एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो इसे संसद के समक्ष रखेगा और राज्यों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को प्रस्तुत करेगा जो इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखेंगे।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 इस कार्यालय के अधिकार को स्थापित करता है।



- The CAG is not eligible for any further office after the end of their tenure either in the Government of India or any State Government.
- The expenses on the administration of this office including all allowances, salaries and pensions would be charged to the Consolidated Fund of India
- सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी और कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।
- सभी भत्तों, वेतनों और पेंशनों सहित इस कार्यालय के प्रशासन पर व्यय भारत की संचित निधि से प्रभारित किया जाएगा।

- Q3. WHO IS THE CURRENT CHAIRMAN OF UPSC COMMISSION?
- Q3. यूपीएससी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?

- A. Shri Pradeep Kumar Joshi श्री प्रदीप कुमार जोशी
- B. Shri Bhim Sain Bassi श्री भीम सेन बस्सी
- C. Ms. Sujata Mehta सुश्री सुजाता मेहता
- D. Dr. Manoj Soni डॉ. मनोज सोनी

## ANSWER : A SHRI P.K JOSHI

- **On 7th August 2020, Pradeep Kumar Joshi has been appointed as the chairman of UPSC. He was earlier a member of the UPSC.**
- Union Public Service Commission (UPSC) is not an exam but it is a constitutional body which is authorized to conduct various exams in the country
- 7 अगस्त 2020 को प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले यूपीएससी के सदस्य थे।
- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) एक परीक्षा नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो देश में विभिन्न परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है।

- The commission's approval is granted by the Constitution of India as mentioned in the articles 315 to 323 of Part XIV of the constitution titled as Services under the Union and the States for public service commission for the union and for each state.
- The Union Public Service Commission (UPSC) consists of a chairman and ten members.
- at lea
- Each member holds office for a term of 6 years or until he attains the age of 65 years.st 10 years of experience either in Central or State service.

- आयोग की स्वीकृति भारत के संविधान द्वारा दी गई है, जैसा कि संघ और राज्यों के तहत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के लिए सेवाओं के रूप में शीर्षक वाले संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लेख किया गया है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं।
- ली पर
- प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। केंद्रीय या राज्य सेवा में 10<sup>3</sup> वर्ष का अनुभव।



- Q4. WHAT COMES UNDER ARTICLE 280 ?
- प्रश्न4. अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आता है?
  - A. FINANCE COMMISSION वित्त आयोग
  - B. INTERSTATE COMMISSION अंतरराज्यीय आयोग
  - C. UPSC
  - D. NONE

## ANSWER : A

- Finance Commission is a constitutional body for the purpose of allocation of certain revenue resources between the Union and the State Governments.
- It was established under Article 280 of the Indian Constitution by the Indian President. It was created to define the financial relations between the Centre and the states. It was formed in 1951
- every 5 years, has to constitute a Finance Commission of India.
- वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में हुआ था
- हर 5 साल में, भारत के वित्त आयोग का गठन करना होता है।

- Chairman: Heads the Commission and presides over the activities. He should have had public affairs experience.
- Four Members.
- All the appointments are made by the President of the country.
- अध्यक्ष: आयोग का प्रमुख और गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए था।
- चार सदस्य।
- सभी नियुक्तियां देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

- Q5. INTERSTATE COUNCIL COMES UNDER WHICH ARTICLE ?
- प्रश्न5. अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है ?

- A. ART262
- B. ART263
- C. ART265
- D. ART266

## ANSWER : B

- Article 263 of the Indian constitution gives provision for the establishment of an Inter-State Council.
- The nation can progress only if the Union and State Governments work hand in hand.
- Inter-State Council is not a permanent constitutional body, which can be created at any time if it seems to the President that the public interest would be served by the establishment of such council.
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
- देश तभी आगे बढ़ सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें साथ-साथ काम करें।
- अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसे किसी भी समय बनाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से जनहित की सेवा होगी।



- Prime Minister acts as the chairman of the council
- Union Ministers of Cabinet rank in the Union
- Council of Ministers nominated by the Prime Minister.
- Chief Ministers of all states.
- Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly
- Administrators of UTs not having a Legislative Assembly.
- Governors of the states being administered under President's rule.
- प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है
- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री संघ में रैंक
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिपरिषद।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनके पास विधान सभा नहीं है।
- राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के तहत प्रशासित किए जा रहे हैं।

- Q6. WHO CONDUCT THE THE FREE AND FAIR ELECTION IN INDIA?
- प्रश्न6. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन करवाता है?

- A. UPSC
- B. FINANCE COMMISSION वित्त आयोग
- C. ELECTION COMMISSION चुनाव आयोग
- D. INTERSTATE COUNCIL अंतरराज्यीय परिषद

## ANSWER : C

- The Constitution of India has established a permanent and independent body to ensure free and fair elections in the country known as the Election Commission Article 324
- Since its inception in 1950 and till 15 October 1989, the election commission was a one-member body with only the Chief Election Commissioner (CEC) as its sole member. भारत के संविधान ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की है जिसे चुनाव आयोग के अनुच्छेद 324 के रूप में जाना जाता है।
- 1950 में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर 1989 तक, चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, जिसका एकमात्र सदस्य केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) था।

- On 16 October 1989, the voting age was changed from 21 to 18 years. So, two more election commissioners were appointed by the president in order to cope with the increased work of the election commission.
- the Election Commission was a multi-member body that consisted of 3 election commissioners.
- the same powers and emoluments including salaries, which are the same as a Supreme Court judge.
- 16 अक्टूबर 1989 को मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। इसलिए, चुनाव आयोग के बढ़े हुए कामों से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई।
- चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय था जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल थे।
- वेतन सहित समान शक्तियां और परिलब्धियां, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

- The office is held by them for a term of 6 years or until they attain 65 years
- कार्यालय उनके द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं



- Q7. WHICH ARTICLE DEALS WITH THE VICE PRESIDENT ?
- प्रश्न 7. कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है?

- A. Art 63
- B. Art60
- C. Art61
- D. Art55

## Answer : a ARTICLE 63

- The post of Vice-President of India is modelled on the lines of American Vice-President. In India, Vice-President has the second-highest office in the country
- भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का देश में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है

- In electoral college for Vice President, both elected and nominated members of both the Houses of Parliament take part. In presidential elections, nominated members are not a part of the electoral college.
- For Vice President's elections, states have no role to play unlike in President's elections where state legislative assemblies' elected members are a part of the electoral college.
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनावों में, मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं।
- उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए, राज्यों की राष्ट्रपति चुनावों के विपरीत कोई भूमिका नहीं होती है, जहां राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं।

- An Indian citizen can qualify for the post of Vice President if he is 35 years old or more. Another qualification for a candidate to run for vice-presidential elections is to be qualified to be elected as Rajya Sabha member.
- एक भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है यदि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है। उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के लिए एक अन्य योग्यता राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना है।



# CURRENT AFFAIRS

## RANK OF INDIA IN INDEX 2021

- Economic Freedom Index 2021: 121st.
- World Happiness Report 2021: 139th.
- International Intellectual Property (IP) Index 2021: 40th.
- World Press Freedom Index, 2021: 142nd.
- World Competitiveness Index 2021: 43rd.
- Global Peace Index 2021: 135th.
- Global Startup Ecosystem Index 2021: 20th.





Manashree Sarkar · 54 seconds ago (edited)

Tackling Plastic Pollution

Srikant ji From Hyderabad  
DRDO 1958





Akash singh • 1 minute ago (edited)

◆ Kidambi Srikant from Andhra Pradesh ...ranked as world number 1 at the BWF ranking in April 2018. Awarded with Padma Shri, India's fourth highest civilian award in 2018. and Arjuna award in 2015.

◆ DRDO established in 1958 .  
Chairman = G. Satish Reddy

